भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2378

उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

आंध्र प्रदेश में समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन

†2378. **श्री जी. लक्ष्मीनारायण:**

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत देश भर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले सहित जिला-वार कुल कितनी स्मार्ट कक्षाएं और कार्यात्मक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रयोगशालाएं स्वीकृत और स्थापित की गई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त राज्य में आईसीटी उपकरण, स्मार्ट बोर्ड तथा ई-लर्निंग संसाधनों और डिजिटल पहल के घटक सहित डिजिटल अवसंरचना के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा योजना के अंतर्गत पालनाडु जिले में स्वीकृत विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घटक के अंतर्गत स्वीकृत सभी स्कूल पूरी तरह कार्य कर रहे हैं और दीक्षा प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और आंध्र प्रदेश में जिला-वार समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा घटक के अंतर्गत शामिल विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की संख्या कितनी है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान पालनाडु जिले में समावेशी शिक्षा घटक के अंतर्गत विशेष आवश्यकताओं वाली बालिकाओं के लिए चिकित्सीय सहायता, सहायक उपकरण, परिवहन भत्ता, ब्रेल एवं बड़े प्रिंट की पुस्तकें तथा छात्रवृत्ति के लाभार्थियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त अवधि के दौरान उक्त राज्य में समावेशी शिक्षा घटक हेतु आवंटित, जारी एवं उपयोग की गई धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(छ) क्या किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने खरीद अथवा कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं के कारण आईसीटी निधि में देरी अथवा उपयोग न होने की सूचना दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ज) सरकार ग्रामीण और शहरी स्कूलों के बीच डिजिटल अंतर को कम करने और देश में डिजिटल अधिगम सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना - समग्र शिक्षा को कार्यान्वित कर रहा है। समग्र शिक्षा स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक के लिए है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किया जाता है और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

समग्र शिक्षा के आईसीटी और डिजिटल पहल घटक में कक्षा VI से XII तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस घटक के तहत स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'आईसीटी और डिजिटल पहल' के तहत गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित दो विकल्पों मेंउपलब्ध है:

1. **विकल्प I:** इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले आईसीटी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, वे अपनी मांग और आवश्यकता के अनुसार या तो आईसीटी या स्मार्ट कक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। 700 से अधिक नामांकन के मामले में, एक अतिरिक्त आईसीटी प्रयोगशाला पर भी विचार किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास टैबलेट/लैपटॉप/नोटबुक/एकीकृत शिक्षण अधिगम उपकरणों जैसे हार्डवेयर की खरीद के और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ-साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण और

संसाधन सहायता के लिए लोचशीलता है। इसमें स्वीकृत स्कूलों की संख्या के लिए आनुपातिक आधार पर डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट कक्षा, आभासी कक्षा और डीटीएच चैनलों के लिए सहायता शामिल होगी।

1. **विकल्प II**: इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले से ही आईसीटी सुविधा का लाभ उठाया है, वे योजना के मानदंडों के अनुसार स्मार्ट कक्षा/टैबलेट का लाभ उठा सकते हैं।

वित्तीय प्रावधान:

आईसीटी प्रयोगशाला: 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति स्कूल 6.40 लाख रुपये तक का गैर-आवर्ती अनुदान और 2.40 लाख रुपये प्रति स्कूल प्रति वर्ष तक का आवर्ती अनुदान।

वर्ष 2023-24 से, इस योजना के तहत स्कूल नामांकन के आधार पर चरण-वार वित्त पोषण भी प्रदान की जाती है। (संख्या< 100 2.5 लाख रुपये, 100 से 250 के **बीच** संख्या**:** 4.5 लाख रुपये, 250 से 700 के **बीच** संख्या**:** 6.4 लाख रुपये)

स्मार्ट कक्षाएं: स्मार्ट **कक्षाओं**(प्रति स्कूल 2 स्मार्ट क्लासरूम) के लिए गैर-आवर्ती अनुदान 2.40 लाख रुपये है और आवर्ती अनुदान 38,000/- रुपये प्रति स्कूल प्रति वर्ष है (ई सामग्री और डिजिटल संसाधन, बिजली के लिए शुल्क सहित।

वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत और कार्यात्मक आईसीटी प्रयोगशालाओं का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I में दिया गया है**। वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत और कार्यरत स्मार्ट कक्षाओं का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र -वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II में दिया गया है।"** आंध्र प्रदेश राज्य में कार्यात्मक आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं का जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-III में दिया गया है।** पिछले 5 वर्षों में आईसीटी और स्मार्ट कक्षाओं के लिए आंध्र प्रदेश को स्वीकृत निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

रुपये लाख में

आईसीटी					
आंध्र प्रदेश	**2025-26**	**2024-25**	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**
अनुमोदित	273.9	3228.2	2192.0	4544.0	5868.8

व्यय*	0.0	0.0	19652.7	4400.6	2725.1
स्मार्ट कक्षा					
आंध्र प्रदेश	**2025-26**	**2024-25**	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**
अनुमोदित	3607.2	1405.2	7552.8	1044.0	2630.4
व्यय*	0.0	33.6	10377.6.	849.6	0.0

स्रोत: प्रबंध

** व्यय में स्पिलओवर शामिल है*

दीक्षा- एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म: ज्ञान साझाकरण के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा (दीक्षा), देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री और सभी ग्रेड के लिए क्यूआर कोडेड एनरजाइज्ड पाठ्यपुस्तकें (ईटीबी) प्रदान करता है। दीक्षा में एक भागीदार के रूप में, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों /स्वायत्त निकाय ने बहुभाषावाद को सक्षम बनाने वाली स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.7 लाख से अधिक सामग्री तैयार की है और योगदान दिया है। कुल मिलाकर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 565.28 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए गए हैं। दीक्षा पर 450 से अधिक आभासी प्रयोगशाला और 100 आभासी कौशल प्रयोगशाला (हिंदी और अंग्रेजी में प्रत्येक 50) तक हितधारकों की पहुंच है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य विशिष्ट रूप से दीक्षा प्लेटफॉर्म का लाभ उठाता है और शिक्षकों, शिक्षार्थियों और प्रशासकों के लिए कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अपनी विविध क्षमताओं और समाधानों को अपनाने की स्वायत्तता है। दीक्षा देश भर के छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश के लगभग 99.4 प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी है।

(**घ**) पिछले तीन वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा घटक के अंतर्गत शामिल किए गए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्ड्क-IV में दी गई है**

समग्र शिक्षा के तहत, आंध्र प्रदेश सरकार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार पूर्व-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। आन्ध्र प्रदेश राज्य में पिछले तीन के दौरान समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा घटक के अंतर्गत शामिल किए गए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जिला-वार संख्या **अनुलग्नक-V में दी गई है**

(ङ) आंध्र प्रदेश सरकार भी पलनाडु जिले में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए प्राथमिक स्तर पर मनोचिकित्सकों और माध्यमिक स्तर पर विशेष शिक्षा आदि में स्कूल सहायकों की नियुक्ति करके स्कूल सुलभता कार्यक्रम, परिवहन भत्ता, एस्कॉर्ट भत्ता, सीडब्ल्यूएसएन लड़कियों के लिए वजीफा, घर आधारित शिक्षा, सहायता सामग्री और उपकरण, चिकित्सा मूल्यांकन, खेल और क्रीड़ा, फिजियोथेरेपी सेवाएं टैब प्रदान करके और अधिगम के परिणामों में सुधार करके डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रही है । पलनाडु जिले में लाभाथयों का ब्यौरा **अनुलग्नक-VI में दिया गया है।**

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा घटक के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक -VII में दिया गया है।**

(छ) स्मार्ट कक्षा जैसे डिजिटल मध्य वर्तनों को लागू करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियां या सीमाएं शिक्षकों का क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे की स्थापना, निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि हैं।

वर्ष 2025-26 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों में अनुमोदित यूडीआईएसई+ डेटा और निधि के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं और आईसीटी प्रयोगशालाओं को कार्यात्मक बनाने में कमियों की पहचान की गई थी। इस अंतर को दूर करने के लिए, 10 जून, 2025 को एक पूरक पीएबी आयोजित किया गया था, जिसमें इन सुविधाओं को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश सहित 32 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 20,553 आईसीटी प्रयोगशालाओं और 29,910 स्मार्ट कक्षा को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के लिए 8 नवंबर, 2024 को आयोजित पीएबी में सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) को कार्यात्मक बनाने के लिए 3,564 आईसीटी प्रयोगशालाएं और 3,655 स्मार्ट कक्षाएं अनुमोदित की गयी थी।

भारत सरकार ने बजट 2025-26 में बीएसएनएल द्वारा दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे का प्रसार करने के लिए 'भारतनेट' परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान की घोषणा की है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सलाह दी गई है कि वे छात्रों और शिक्षकों की मांगों को पूरा करने के लिए प्रत्येक स्थान पर मौजूदा स्थिति के आधार पर कार्य करें ताकि उन्हें डिजिटल रूप से अधिगम के लिए आवश्यक डिजिटल पहुंच प्रदान की जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल बुनियादी ढांचे, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म और उपकरण, आभासी प्रयोगशाला, डिजिटल रिपॉजिटरी, ऑनलाइन मूल्यांकन, ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी और शिक्षाशास्त्र आदि में निवेश का आह्वान किया गया है जिसके लिए विभिन्न पहल की गई हैं। स्कूल शिक्षा के लिए, एनईपी 2020 के अनुरूप सभी राज्यों/संघ राज्य के लिए समग्र शिक्षा के तहत आवश्यक वित्त पोषण तंत्र के साथ छात्रों, शिक्षकों और सभी हितधारकों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है।

(ज) एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने और शिक्षा में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल है जो शिक्षा के लिए बहुआयामी पहुंच को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है, जिसका लक्ष्य आंध्र प्रदेश सहित देश भर में स्कूल जाने वाले लगभग 25 करोड़ बच्चों को लाभान्वित करना है। इस पहल के प्रमुख घटक दीक्षा - देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा , 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करना, डिजिटल पुस्तकों और ई-सामग्री के प्रसार के लिए ई-पाठशाला पहल, ई जादुई पिटारा भौतिक जादुई पिटारा के लिए सहायक और पूरक डिजिटल ऐप, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आभासी प्रयोगशाला में निर्मित एक वर्टिकल जहां कक्षा 6वीं से 12वीं के विषयों के लिए विज्ञान और गणित के लिए आभासी प्रयोगशाला उपलब्ध कराई गई हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की उपरोक्त डिजिटल पहल, विशेष रूप से "आईसीटी और स्मार्ट कक्षा घटक" छात्रों को बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और कक्षा को तकनीक-संचालित कक्षा में क्रियाशील बनाते हैं। छात्र मल्टीमीडिया सामग्री और इंटरैक्टिव गतिविधियों के साथ जुड़ाव बढ़ाते हैं और संसाधनों की व्यापक श्रृंखला का लाभ उठाते हैं। यह छात्रों के लिए गहरी समझ, सहयोग और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है, जिससे उनके समग्र शैक्षिक अनुभव को समृद्ध किया जा सकता है।

******

अनुलग्नक-I

'आंध्र प्रदेश में समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जी. लक्ष्मी नारायण, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू और श्री जी.एम. हरीश बालयोगी द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2378 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष	**2025-26**		**2024-25**		**2023-24**		**2022-23**		**2021-22**	
राज्य	**अनुमोदन**	**कार्यात्मक***	**अनुमोदन**	**कार्यात्मक**	**अनुमोदन**	**कार्यात्मक**	**अनुमोदन**	**कार्यात्मक**	**अनुमोदन**	**कार्यात्मक**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16	1	3	3	6	6	8	8	2	2
आंध्र प्रदेश	69	0	562	0	405	405	710	710	917	917
अरुणाचल प्रदेश	162	0	92	66	114	0	39	27	43	43
असम	1414	0	83	0	0	0	645	645	1859	1859
बिहार	1459	555	627	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	16	32	32	0	1	1	0	0	2	2
छत्तीसगढ	3188	0	1436	0	352	352	0	0	67	67
डीएनडी - डीएनएच	10	11	12	0	24	24	25	24	28	28
दिल्ली	778	0	249	0	0	0	7	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
गुजरात	67	21	35	249	479	1	0	0	0	0
हरियाणा	1097	32	72	20	255	4	113	0	232	8
हिमाचल प्रदेश	561	0	3	3	12	0	282	0	480	0
जम्मू और	534	0	598	0	172	0	203	202	220	220

कश्मीर										
झारखंड	125	21	286	8	1447	1174	504	485	896	887
कर्नाटक	759	4	454	0	0	0	0	0	764	501
केरल	79	0	1	0	0	0	0	0	0	0
लद्दाख	13	1	17	2	46	46	16	15	6	6
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	3899	105	889	37	879	879	0	0	441	441
महाराष्ट्र	921	0	331	0	309	309	0	0	0	0
मणिपुर	169	30	42	0	52	52	34	33	28	28
मेघालय	79	0	55	43	29	29	28	28	25	25
मिजोरम	131	0	311	0	217	217	62	62	0	0
नगालैंड	51	0	22	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	1672	0	95	0	0	0	0	0	302	302
पुदुचेरी	82	0	0	0	0	0	0	0	6	6
पंजाब	1093	2	125	0	719	0	559	0	435	0
राजस्थान	2657	0	998	0	937	0	412	403	398	398
सिक्किम	0	0	10	0	3	0	0	0	82	82
तमिलनाडु	2166	0	1078	0	3536	3536	2211	2211	1893	1893
तेलंगाना	1242	0	562	332	640	0	94	93	0	0
त्रिपुरा	341	0	91	76	105	105	294	294	239	239
उत्तर प्रदेश	9278	0	2353	12	3669	6	289	0	0	0
उत्तराखंड	215	0	28	0	0	0	0	0	240	0
पश्चिम बंगाल	0	0	160	0	63	0	0	0	1173	0
कुल	**34343**	**815**	**11712**	**851**	**14474**	**7146**	**6535**	**5240**	**10778**	**7954**

स्रोत : प्रबंध

**वर्ष 2025-26 के लिए कार्यात्मक, जिसमें 10 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार स्पिल ओवर प्रगति शामिल है*

अनुलग्नक-।।

'आंध्र प्रदेश में समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जी. लक्ष्मी नारायण, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू और श्री जी.एम. हरीश बालयोगी द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2378 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष	2025-26		2024-25		2023-24		2022-23		2021-22	
राज्य	अनुमोदन	कार्यात्मक*	अनुमोदन	कार्यात्मक	अनुमोदन	कार्यात्मक	अनुमोदन	कार्यात्मक	अनुमोदन	कार्यात्मक
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	1503	0	659	14	3147	3147	435	434	1096	1096
अरुणाचल प्रदेश	102	0	34	34	102	0	107	107	0	0
असम	665	475	897	152	1701	1	240	240	3643	3643
बिहार	6113	0	627	0	1981	0	126	126	2739	2701
चंडीगढ़	0	0	1	1	1	1	95	95	89	89
छतीसगढ	332	0	4582	0	519	519	0	0	2714	2714
डीएनडी - डीएनएच	0	0	37	0	18	0	53	53	84	84
दिल्ली	4577	0	0	0	90	0	45	45	906	895
गोवा	63	0	0	0	0	0	0	0	24	24
गुजरात	0	0	521	444	447	447	0	0	4372	4372
हरियाणा	0	0	211	0	424	306	342	342	115	1154

									4	
हिमाचल प्रदेश	596	0	14	0	0	0	616	616	1632	1632
जम्मू और कश्मीर	1001	0	1703	0	372	0	834	834	518	518
झारखंड	1140	259	337	0	342	342	121	121	519	519
कर्नाटक	2136	0	95	0	100	0	1768	437	0	0
केरल	242	0	23	0	115	1	257	257	115	115
लद्दाख	33	1	66	56	20	20	8	8	38	38
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	4042	384	3716	189	3457	2471	658	658	700	700
महाराष्ट्र	2463	0	42	0	209	0	2405	2233	887	24
मणिपुर	21	19	36	0	57	57	140	140	311	311
मेघालय	0	0	3	3	0	0	14	14	0	0
मिजोरम	4	0	11	0	0	0	28	28	201	201
नगालैंड	0	0	63	0	13	13	47	47	74	74
ओडिशा	4121	0	681	0	0	0	2119	2119	4471	4470
पुदुचेरी	7	0	0	0	0	0	45	45	100	100
पंजाब	43	1	18	0	300	0	664	664	2903	2903
राजस्थान	3834	0	430	0	3420	5	408	408	5509	3910
सिक्किम	0	0	27	27	0	0	32	32	238	238
तमिलनाडु	2683	0	6284	0	0	0	0	0	865	865
तेलंगाना	2036	0	505	275	697	697	0	0	3010	3010
त्रिपुरा	261	0	47	32	42	42	563	563	249	249

उत्तर प्रदेश	6727	0	4590	0	4229	16	18444	18444	543	0
उत्तराखंड	307	0	11	0	78	0	195	102	709	0
पश्चिम बंगाल	79	0	502	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**45180**	**1139**	**26773**	**1227**	**21881**	**8085**	**30809**	**29212**	**40413**	**36649**

स्रोत : प्रबंध

**वर्ष 2025-26 के लिए कार्यात्मक, जिसमें 10 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार स्पिल ओवर प्रगति शामिल है*

अनुलग्नक-।।।

'आंध्र प्रदेश में समग्र शिक्षा योजना के कार्यान्वयन' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जी. लक्ष्मी नारायण, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू और श्री जी.एम. हरीश बालयोगी द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2378 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश के स्कूलों में उपलब्ध डिजिटल अवसंरचना का जिला-वार ब्यौरा

जिलावार (आंध्र प्रदेश) आईसीटी और स्मार्ट क्लासरूम - 2024-25					
राज्य	**जिले**	**जिले में स्कूलों की कुल संख्या**	**संख्या**		
			इंटरनेट	**आईसीटी या कंप्यूटर लैब**	**स्मार्ट क्लासरूम**
आंध्र प्रदेश	अनकापल्ली	411	411	191	313
	अनंतपुर	541	527	150	416
	अन्नमय्या	476	474	150	329
	अस्र	393	372	137	275
	बापतला	296	296	96	225
	चित्तूर	537	537	170	371
	पूर्वी गोदावरी	281	281	63	211
	एलुरु	434	432	90	320
	गुंटूर	220	220	67	166
	कडपा	410	410	140	319
	काकीनाडा	351	351	121	281
	कोनासीमा	313	313	70	244
	कृष्ण	360	360	154	292
	कुरनूल	478	478	80	434
	मन्याम	296	296	121	220
	नांदयाल	397	397	91	323
	नेल्लोर	554	553	137	423
	एनटीआर	297	292	88	224

	पलनाडु	**389**	**389**	**140**	**328**
	प्रकाशम	563	563	220	445
	श्री सत्यसाई	505	490	150	370
	श्रीकाकुलम	725	725	189	546
	तिरुपति	471	471	120	355
	विशाखापत्तनम	150	150	62	122
	विजयनगरम	488	485	140	474
	पश्चिम गोदावरी	310	310	71	237
	कुल	**10646**	**10583**	**3208**	**8263**

स्रोत: यूडाइस + 2024-25

अनुलग्नक-IV

'आंध्र प्रदेश में समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जी. लक्ष्मी नारायण, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू और श्री जी.एम. हरीश बालयोगी द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2378 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा घटक के तहत कवर किए गए विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	595	527	741	724	772
आंध्र प्रदेश	88252	92262	88502	76620	89608
अरुणाचल प्रदेश	3289	3038	3006	3007	3089
असम	59596	55243	58890	56841	56454
बिहार	141314	177989	163322	165343	181200
चंडीगढ़	3492	3755	3891	4050	3602
छत्तीसगढ	67768	77249	79619	83719	73645
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2493	1178	1137	1126	1201
दिल्ली	29178	27026	22530	35877	38384
गोवा	2099	3779	4538	4341	4571
गुजरात	81616	73912	67072	62121	61569
हरियाणा	25828	25718	22418	19352	21625
हिमाचल प्रदेश	6751	6864	6463	5984	6170
जम्मू और कश्मीर	22736	19867	19054	17993	20534
झारखंड	53118	51665	35765	49346	50126
कर्नाटक	98371	98961	100482	88701	85872
केरल	139443	138413	134223	123877	123600
लद्दाख	572	1052	630	622	626
लक्षद्वीप	267	208	194	198	190
मध्य प्रदेश	121475	139258	143560	146932	153821

महाराष्ट्र	280574	260251	243496	234489	233791
मणिपुर	4451	4759	4183	4065	4265
मेघालय	4975	4601	3888	3252	3421
मिजोरम	4195	3976	4057	3874	3828
नगालैंड	2280	4084	2458	1667	1744
ओडिशा	103058	146512	97030	93467	91631
पुदुचेरी	1675	2288	1543	1219	1235
पंजाब	67483	66776	61302	51415	53761
राजस्थान	84059	80910	80790	69591	70200
सिक्किम	1555	1320	1130	1025	998
तमिलनाडु	163570	156359	140842	142697	140803
तेलंगाना	43680	40014	33063	81240	72672
त्रिपुरा	3700	3914	3949	3243	3318
उत्तर प्रदेश	317212	327385	322969	316406	333862
उत्तराखंड	5285	5080	4680	4645	5209
पश्चिम बंगाल	155193	160599	145795	155041	151861
कुल योग	2191198	2266792	2107212	2114110	2149258

स्रोत: यूडाइस + 2024-25

अनुलग्नक-V

'आंध्र प्रदेश में समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जी. लक्ष्मी नारायण, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू और श्री जी.एम. हरीश बालयोगी द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2378 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा घटक के तहत कवर किए गए विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की ज़िलेवार संख्या

एस.नं.	जिलों	वर्ष		
		2022-23	2023-24	2024-25
1	अनकापल्ली	2553	2708	2209
2	अनंतपुर	3395	3778	3151
3	अन्नमय्या	2807	2883	2351
4	ए एस आर	1324	1270	860
5	बापतला	2552	2472	2089
6	चित्तूर	3178	3380	2742
7	पूर्वी गोदावरी	2404	2460	2075
8	एलुरु	3681	3291	2804
9	गुंटूर	2134	2801	2476
10	काकीनाडा	3156	3079	2612
11	कोनासीमा	2287	2387	1963
12	कृष्णा	2567	2612	2224
13	कुरनूल	3759	3872	3283
14	मन्याम	1564	1659	1327
15	नांदयाल	3602	3705	3162
16	नेल्लोर	3317	3410	2833
17	एनटीआर	2020	2056	1728
18	पलनाडु	3269	2974	2525
19	प्रकाशम	3425	3362	2744
20	श्री सत्यसाई	3023	3136	2589

एस.नं.	जिलों	वर्ष		
		2022-23	2023-24	2024-25
21	श्रीकाकुलम	3865	4584	3827
22	तिरुपति	3211	3095	2531
23	विशाखापत्तनम	1419	1549	1340
24	विजयनगरम	3313	3347	2803
25	पश्चिम गोदावरी	2701	2660	2245
26	वाईएसआर कडप्पा	3286	3183	2655

स्रोत: आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी

अनुलग्नक-V।

'आंध्र प्रदेश में समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जी. लक्ष्मी नारायण, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू और श्री जी.एम. हरीश बालयोगी द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2378 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों में पालनाडु जिले में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा घटक के अंतर्गत परिवहन भत्ता, अनुरक्षण भत्ता, सीडब्ल्यूएसएन बालिका वजीफा, गृह आधारित भत्ता, पाठक भत्ता, सीडब्ल्यूएसएन (ब्रेल किट) ब्रेल लिपि तथा फिजियोथेरेपी के सहायक सामग्री एवं उपकरण के लाभार्थियों का ब्यौरा।

समग्र शिक्षा : : पालनाडू जिला							
सीब्डब्ल्यूएसएन भत्ते के लाभार्थी							
क्रम सं.	**वर्ष**	**परिवहन भत्ते**	**अनुरक्षण**	**लड़कियों का वजीफा**	**घर आधारित**	**पाठक भत्ता**	**ब्रेल किट**
1	2022- 2023	547	630	698	180	20	10
2	2023-2024	847	712	1198	180	185	10
3	2024-2025	728	641	1389	280	प्रस्तावित नहीं	10
4	2025-2026	267	332	674	217	प्रस्तावित नहीं	10

स्रोत: आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी

समग्र शिक्षा : : पालनाडू जिला				
क्रम सं.	**वर्ष**	**फिजियोथेरेपी प्राप्त करने वाले सीडब्ल्यूएसएन की संख्या (प्रति माह)**	**फिजियोथेरेपी प्राप्त करने वाले सीडब्ल्यूएसएन की संख्या (प्रति वर्ष)**	**कार्यरत फिजियोथेरेपिस्टों की संख्या**
1	2022- 2023	153	1530	5

2	2023-2024	153	1530	5
3	2024-2025	194	1940	5
4	2025-2026	241	2410	8

स्रोत: आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी

अनुलग्नक-VII

'आंध्र प्रदेश में समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जी. लक्ष्मी नारायण, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू और श्री जी.एम. हरीश बालयोगी द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2378 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(राशि रु. में)

	वर्ष	**2022-23**			**2023-24**			**2024-25**		
क्रम	**ज़िला**	**स्वीकृत बजट**	**बजट निर्मुक्ति**	**व्यय**	**स्वीकृत बजट**	**बजट निर्मुक्ति**	**व्यय**	**स्वीकृत बजट**	**बजट निर्मुक्ति**	**व्यय**
1	**अल्लूरी सीता राम राजू**	468,200	468,200	468,200	14,429,000	14,429,000	7,397,225	16,058,500	16,058,500	9,128,414
2	**अनकापल्ली**	633,598	633,598	633,598	25,148,500	25,148,500	10,792,324	13,908,500	13,908,500	12,585,432
3	**अनंतपुर**	14,752,391	14,752,391	14,752,391	25,121,500	25,121,500	14,323,908	13,099,500	13,099,500	11,827,029
4	**अन्नमय**	457,370	457,370	457,370	22,721,500	22,721,500	9,044,974	6,743,000	6,743,000	5,558,348
5	**बापतला**	991,350	991,350	991,350	21,197,000	21,197,000	10,258,440	12,402,000	12,402,000	9,595,529
6	**पश्चिम गोदावरी**	589,998	589,998	589,998	19,076,000	19,076,000	9,802,289	10,208,000	10,208,000	8,935,556
7	**चित्तूर**	14,350,822	14,350,822	14,350,822	24,704,000	24,704,000	12,005,973	13,524,000	13,524,000	10,075,133
8	**एलुरु**	16,002,751	16,002,751	16,002,751	26,802,500	26,802,500	12,603,276	15,430,500	15,430,500	12,653,554
9	**गुंटूर**	14,857,561	14,857,561	14,857,561	16,108,500	16,108,500	6,831,482	7,852,500	7,852,500	9,588,179
10	**कडपा**	11,245,111	11,245,111	11,245,111	28,039,500	28,039,500	13,059,321	19,185,500	19,185,500	9,807,922
11	**काकीनाडा**	12,118,220	12,118,220	12,118,220	19,685,500	19,685,500	10,795,705	10,604,500	10,604,500	9,474,925

	वर्ष	2022-23			2023-24			2024-25		
क्रम	ज़िला	स्वीकृत बजट	बजट निर्मु	व्यय	स्वीकृत बजट	बजट निर्मु	व्यय	स्वीकृत बजट	बजट निर्मु	व्यय
12	कोनासीमा	869,961	869,961	869,961	17,970,000	17,970,000	10,226,982	11,682,000	11,682,000	7,366,082
13	कृष्ण	12,028,344	12,028,344	12,028,344	22,259,000	22,259,000	7,881,933	14,137,000	14,137,000	10,802,552
14	कुरनूल	10,812,550	10,812,550	10,812,550	28,327,500	28,327,500	12,893,526	14,805,500	14,805,500	8,958,155
15	मन्याम	257,910	257,910	257,910	15,321,000	15,321,000	6,572,301	8,826,000	8,826,000	9,496,400
16	नांदयाल	530,055	530,055	530,055	27,937,000	27,937,000	13,352,304	17,269,000	17,269,000	12,138,634
17	नेल्लोर	7,023,316	7,023,316	7,023,316	29,232,500	29,232,500	13,212,655	18,874,000	18,874,000	10,762,900
18	एनटीआर	275,874	275,874	275,874	15,200,000	15,200,000	6,853,860	8,358,000	8,358,000	9,880,666
19	पलनाडु	1,932,982	1,932,982	1,932,982	27,449,000	27,449,000	9,650,496	13,968,000	13,968,000	10,807,180
20	प्रकाशम	12,254,180	12,254,180	12,254,180	30,729,500	30,729,500	16,772,731	19,554,500	19,554,500	9,543,733
21	पूर्वी गोदावरी	-	-	-	17,774,000	17,774,000	8,781,725	9,616,000	9,616,000	6,156,889
22	सत्य साईं	328,891	328,891	328,891	26,063,500	26,063,500	23,145,404	16,554,500	16,554,500	14,114,147
23	श्रीकाकुलम	8,759,146	8,759,146	8,759,146	30,147,500	30,147,500	14,591,902	18,485,500	18,485,500	15,663,770
24	तिरुपति	821,158	821,158	821,158	29,069,500	29,069,500	13,831,989	17,927,500	17,927,500	69,793,289
25	विशाखापत्तनम	7,644,060	7,644,060	7,644,060	10,316,500	10,316,500	4,773,974	5,119,500	5,119,500	5,512,199
26	विजयनगरम	9,238,237	9,238,237	9,238,237	26,332,500	26,332,500	11,840,450	15,793,500	15,793,500	13,637,291

	वर्ष	2022-23			2023-24			2024-25		
क्रम	ज़िला	स्वीकृत बजट	बजट निर्मु	व्यय	स्वीकृत बजट	बजट निर्मु	व्यय	स्वीकृत बजट	बजट निर्मु	व्यय
	कुल	159,244,037	159,244,037	159,244,037	597,162,500	597,162,500	291,297,149	349,987,000	349,987,000	323,863,905

स्रोत: आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी